भूमि पूजन का लक्ष्य हासिल करने वाला पहला विभाग बना सहकारिता

जीबीसी के लिए तय पांच हजार करोड़ के निवेश लक्ष्य को किया पार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए निवेश करारों को जमीन पर उतारने की विभागीय होड़ में सहकारिता विभाग ने प्रदेश के तमाम विभागों को पीछे छोड़ दिया है। सहकारिता विभाग ने सितंबर-अक्टूबर में प्रस्तावित पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) के लिए तय निवेश लक्ष्य को पार कर लिया है। विभाग से एमओयू करने वाले 126 निवेशक शिलान्यास के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

यूपीजीआइएस के दौरान सहकारिता विभाग से 191 निवेशकों ने 13,767 करोड़ रुपये के निवेश करार किए थे। इनमें 5147 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 126 निवेशक शिलान्यास समारोह के लिए तैयार हैं। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए सहकारिता विभाग को पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश लक्ष्य दिया गया है, इस लिहाज से जीबीसी को लेकर विभाग की उपलब्धि 103 प्रतिशत आंकी गई है। हालांकि, हाल ही में जीबीसी के लिए विभागीय लक्ष्यों को संशोधित करने के क्रम में सहकारिता विभाग का संशोधित

विभाग से एमओयू करने वाले 126 इकाइयां शिलान्यास को हैं तैयार

लक्ष्य भी बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपये किया गया है, उस लिहाज से विभाग की उपलब्धि 69 प्रतिशत है।

जमीन पर उतरने वाले प्रमुख निवेश करारों की बात करें तो 638 करोड़ रुपये की लागत से इफको नैनो यूरिया प्रोजेक्ट लगाएगी। वहीं, 1116 करोड़ रुपये की लागत से शुगर व एथेनाल प्रोजेक्ट के लिए यूपी कोआपरेटिव बैंक कर्ज उपलब्ध कराएगा। राज्य भंडारण निगम के साथ 1369 करोड़ रुपये के 48 वेयरहाउस प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे, जबकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत विभिन्न इकाइयां 482 करोड़ रुपये की लागत से 35 वेयरहाउस प्रोजेक्ट लगाएंगी। 26 निजी इकाइयों ने भी 1542 करोड़ की लागत से वेयर हाउस प्रोजेक्ट में निवेश का भरोसा दिलाया है। अन्य विभागों की तरह सहकारिता विभाग को भी अपने निवेश करारों को धरातल पर उतारने में भूमि की समस्या का समाना करना पड़ रहा है।

डेढ़ लाख पटरी दुकानदारों को प्रधानमंत्री देंगे स्वनिधि योजना का लाभ

राब्यू, लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सात जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रदेश भर के करीब डेढ़ लाख पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ प्रदान करेंगे। पटरी दुकानदारों के बैंक खाते में सीधे कर्ज की धनराशि भेजी जाएगी। नगर विकास विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी नगरीय निकायों को पटरी दुकानदारों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान आजीविका खो चुके रेहड़ी व पटरी दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर यह योजना शुरू की गई थी। इसमें पहला कर्ज 10 हजार रुपये का मिलता है।